

80 दिन की आचार संहिता और बदलती चुनावी संस्कृति: राजस्थान ने दिखाई नई राह



अलका सक्सेना

लोकतंत्र में चुनाव जनभागीदारी और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। लेकिन चुनावों की प्रक्रिया यदि लगातार चलती रहे और उसका प्रभाव महीनों तक शासन-प्रशासन की सामान्य कार्यप्रणाली पर बना रहे तो उसका सीधा असर विकास की गति पर पड़ता है। राजस्थान जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में यह चुनौती और भी बड़ी है। ऐसे में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को एक समन्वित प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय केवल चुनावी प्रबंधन का विषय नहीं, बल्कि सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में इस बार स्थानीय लोकतंत्र के इतने बड़े चुनावी दायरे को सीमित अवधि में समेटने का प्रयास हुआ है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 80 दिन की आचार संहिता की अवधि में 3०9 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दायित्व को पूरा करने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है। इन 3०9 नगरीय निकायों में 1० नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल हैं तथा 1०,245 पंचायत पदों पर चुनाव होना है। साथ ही 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,4०3 ग्राम पंचायतों में भी चुनाव है। पिछली बार स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की प्रक्रिया लगभग 15 महीने तक अलग-अलग चरणों और अलग-अलग समय में

चलती रही। इसका अर्थ केवल इतना नहीं था कि राजनीतिक दल लंबे समय तक चुनावी मोड़ में रहे। इसका बड़ा प्रभाव शासन-प्रशासन पर भी पड़ा। जब चुनाव लगातार अलग-अलग संस्थाओं के लिए होते रहें तो आचार संहिता भी बार-बार लागू होती है या लंबे समय तक प्रभावी रहती है। नई योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों की गति स्वाभाविक रूप से प्रभावित होती है। यही वह बिंदु है जहां राजस्थान की वर्तमान चुनावी व्यवस्था को प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखने की आवश्यकता है। किसी भी सरकार के लिए पाँच वर्ष का कार्यकाल सुनरे में लंबा लगता है, लेकिन यदि स्थानीय निकाय, पंचायत, विधानसभा और अन्य चुनाव अलग-अलग समय पर लगातार सामने आते रहें तो वास्तविक शासन अवाधि लगातार कम होती जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम और उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों तक सरकार और प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा चुनावी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहता है। आचार संहिता लोकतांत्रिक निष्पक्षता के लिए आवश्यक है। उसके प्रावधानों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या सरकार को अनुचित लाभ से रोकना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसके दौरान नए कार्यों और नीतिगत निर्णयों पर स्वाभाविक रूप से सीमाएं लगती हैं। इसलिए लोकतंत्र की शुचिता और प्रशासन की निरंतरता के बीच संतुलन आवश्यक है। राजस्थान में इस बार चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय में संपन्न कराने का प्रयास इसी संतुलन की दिशा में दिखाई देता है।

चुनावी प्रक्रिया जितनी समयबद्ध होगी, उतनी ही जल्दी प्रशासन सामान्य कार्यप्रणाली में लौट सकेगा और निर्वाचित स्थानीय संस्थाएं भी अपने दायित्व संपाल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को अधिक समन्वित और कम विखंडित करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उनका व्यापक विचार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दिशा में चुनावी चक्र को समन्वित करने का है। इसी सोच की राज्य स्तर पर व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को एक समन्वित चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की पहल महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावों को एक साथ करने का जो संकल्प व्यक्त किया था, उसे धरातल पर उतारने की दिशा में यह कदम उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ प्रशासनिक सोच को भी दर्शाता है। हाल में मुख्यमंत्री ने स्वयं 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' को सरकार की उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया है। यहां असली महत्व उस सोच का है जिसमें चुनावों को बार-बार होने वाली अलग-अलग प्रशासनिक कवायद के बजाय एक समन्वित प्रक्रिया में बदलने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान का विकास एजेंडा व्यापक है। सड़क, पानी, बिजली, नगरीय आधारभूत ढांचा, ग्रामीण विकास, रोजगार, पर्यटन, औद्योगिक निवेश और सामाजिक कल्याण सहित हर क्षेत्र में निरंतर निर्णय और क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

यदि प्रशासन लंबे समय तक चुनावी दायित्वों में उलझा रहे तो इसका असर केवल सरकारी कार्यालयों तक दल या सरकार को अनुचित लाभ से रोकना है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इसके दौरान नए कार्यों और नीतिगत निर्णयों पर स्वाभाविक रूप से सीमाएं लगती हैं। इसलिए लोकतंत्र की शुचिता और प्रशासन की निरंतरता के बीच संतुलन आवश्यक है। राजस्थान में इस बार चुनावों को अपेक्षाकृत कम समय में संपन्न कराने का प्रयास इसी संतुलन की दिशा में दिखाई देता है।

चुनावी प्रक्रिया जितनी समयबद्ध होगी, उतनी ही जल्दी प्रशासन सामान्य कार्यप्रणाली में लौट सकेगा और निर्वाचित स्थानीय संस्थाएं भी अपने दायित्व संपाल सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया को अधिक समन्वित और कम विखंडित करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उनका व्यापक विचार 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दिशा में चुनावी चक्र को समन्वित करने का है। इसी सोच की राज्य स्तर पर व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को एक समन्वित चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ाने की पहल महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावों को एक साथ करने का जो संकल्प व्यक्त किया था, उसे धरातल पर उतारने की दिशा में यह कदम उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ प्रशासनिक सोच को भी दर्शाता है। यहां असली महत्व उस सोच का है जिसमें चुनावों को बार-बार होने वाली अलग-अलग प्रशासनिक कवायद के बजाय एक समन्वित प्रक्रिया में बदलने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान का विकास एजेंडा व्यापक है। सड़क, पानी, बिजली, नगरीय आधारभूत ढांचा, ग्रामीण विकास, रोजगार, पर्यटन, औद्योगिक निवेश और सामाजिक कल्याण सहित हर क्षेत्र में निरंतर निर्णय और क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। सड़क, नाली, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, स्थानीय विकास और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं जैसे अनेक विषय सीधे इन्हीं संस्थाओं से जुड़े होते हैं।

इसलिए इन संस्थाओं का समय पर गठन लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए आवश्यक है। चुनाव जितनी जल्दी पूरे होंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि उतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारी संपालेंगे और स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं पर काम शुरू कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 3०9 नगरीय निकायों में चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। यह व्यापक चुनावी कवायद अपने आप में प्रशासनिक समन्वय की बड़ी परीक्षा है। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी है। लंबे समय तक चुनाव चलते रहने से राजनीतिक दलों की ऊर्जा लगातार चुनावी गतिविधियों में लगी रहती है।कार्यकर्ता, संगठन और नेतृत्व लगातार एक चुनाव से दूसरे चुनाव की तैयारी में जुड़े रहते हैं।

यदि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव अपेक्षाकृत कम समय में संपन्न हो जाते हैं तो राजनीतिक दलों की भी अपना ध्यान व्यापक संगठनात्मक और नीतिगत कार्यों पर लगाने का अवसर मिलेगा। चुनाव लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है। जनता के बीच लगातार उपस्थित रहना, सरकारों के काम का मूल्यांकन करना, संगठन को मजबूत करना और नीतियों पर संवाद करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का उठना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि किसी भी चुनावी सुधार के सफलता का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि चुनाव जितनी जल्दी हुए। असली कसौटी यह होगी कि चुनाव के बाद निर्वाचित संस्थाएं कितनी प्रभावी ढंग से काम करती हैं और सरकार इस अतिरिक्त प्रशासनिक समय का किताना बेहतर उपयोग करती है।

यदि कम अवधि की आचार संहिता के बाद प्रशासनिक णियों में तेजी आती है, विकास परियोजनाओं की गति बढ़ती है और स्थानीय संस्थाएं प्रोबिओटिक जीवाणुओं को स्थापित तो करती ही हैं अनेक हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट भी कर देती हैं। छाछ पीने वालों के शरीर में कभी मोटापा नहीं आता और न कोलेस्ट्रॉल से उपजे हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। प्रोबिओटिक, लैक्टिक अम्ल, अन्य पेप्टाइड और कम वसा ऐसे गुण हैं जिनकी बराबरी कोई खाद्य नहीं कर सकता।इलाहाबाद कृषि संस्थान में एक अमेरिकन जेम्स वानर कार्यरत थे उन्होंने डेरीइंग इन इंडिया शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उस समय वे अपने को बहुत काबिल देरी टीचर मानते थे, उस पुस्तक में उन्होंने देसी घी और उसके निर्माण के संबंधघ में अनेक बुराईयां लिखीं। दुर्भाग्य ये था तब डेरी शिक्षा व् अनुसन्धान के क्षेत्र में थी थे।इसलिए किसी भी पदार्थ को बुरा बताने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि दोष पदार्थ में है अथवा पदार्थ निर्माता की विधि में।

—**अलका सक्सेना, अतिरिक्त निदेशक जनसंपर्क (से।न.)**

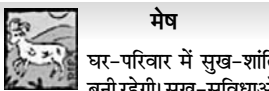
माखन बनाम मक्खन

कैवल देसी घी बनाने की प्रक्रिया में एक बीच का स्टेप तो यह तो रहा दोनों दुध पदार्थों में अंतर जो मूलतः बनाने की विधि तक ही सीमित है हालांकि दोनों प्रक्रियाओं के निर्माण से सम्बन्धित और भी अनेक कारण रहे होंगे और अभी भी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे बाल स्वर्ण भगवान को माखन इतना प्रिय क्यों था कि माँ यशोदा को एक मटकी में भर कर ऊंचे से छींके पर टांग कर रखना पड़ता था इसमें यध्यपि अन्य जानवरों आदि से सुरक्षा भी कारण रहे होंगे। वह एक अलग पहलू है। भले ही माँ सुरक्षा की दृष्टि से माखन को टांग कर रखती हो लेकिन कृष्ण जो तो किसी भी उपाय से उस छींके तक पहुँच माखन खुद भी लपकते और अपने मित्रों को भी सहभागी बना लेते ताकि कोई उनकी शिकायत न कर सके। ये सभी शब्द जो मैंने कहे एक बाल सुलभ शैतानिओं या लीलाओं को ही दर्शाते हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं।

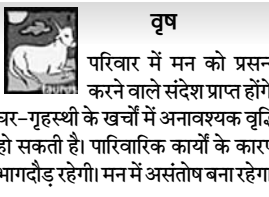
अब बात करते हैं इन दोनों दुग्ध पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और पोषण गुणों की, ऐसा करते समय लेखक का प्रयास होगा माखन पर अपेक्षाकृत अधिक बल जिस पर लोगों का ध्यान कम ही गया है और जिसे लिखा व प्रकाशित भी कम किया गया है। जैसा मैंने बताया कि माखन छोटे स्तर पर अथवा यों कहें ग्रामीणपरिेश के किसान परिवारों में बहुधा घर की कोई महिला बनाती है। श्री कृष्ण की मां यसोदा भी माखन खुद ही बनाती थी ऐसा करते समय कृष्ण जो बहुधा निकट ही कहीं होते तो माँ उस नवीन माखन का एक कौर लल्ला को खिला देती। लल्ला जब और देने की ज़िद

करता तो मां नहीं देती। जानती थी अधिक मात्रा हानि कारक हो सकती है। इस परिदृश्य में फिर भक्त सुदामा कृष्ण के पक्ष में बोल पड़ते हैं “मैया कबहि बड़ेगो छोटी, और मैया में नहीं माखन खायो, मैया ग्वालबाल सब बरवस मुख लिपटायो।” आदि-आदि। ...और भी बहुत कुछ। यहाँ मैं पाठकों को बता दूँ कि यह माखन शायद श्रीकृष्ण के काल से पूर्व भी भारत देश में घर-घर में बनता था। और इसी से देसी घी बनाने की विधा पनपी। यह घी आहार के साथ तो खाय़ा ही जाता था इसका एक पड़ा हिस्सा यज्ञ में आहुति देने में प्रयुक्त होता। यह आज भी वैसे ही चलन में है। माखन के निर्माण में दूध कभी उबाला नहीं जाता अपितु बरोसी (चिकनी मिट्टी, कुछ पिली मिट्टी – पोता, को गुक्कर एक गहरी थालीनुमा चुलेह का बनावर धुप में सूखा लिया जाता है। सुखाने पर इसके अंदर गोबर से बनें सूखे उपले जलाकर दूध को एक

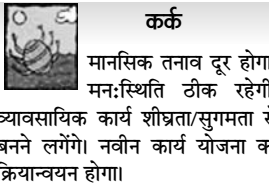
कुम्हार की बानी हांडी में भरकर गर्म किया जाता है जो कब ही उबलता नहीं अपितु उबलने के ताप से नीचे ही कई घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को वैज्ञानिक भाषा में सिमरिंग कहते हैं। इस क्रिया में दूध के हानिकारक जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही दूध के अवयवों से कुछ विशेष तत्व भी पैदा हो जाते हैं। दिन भर सिम्पर किया हुआ दूध ठंडा कर रात को चामन (पूर्वदिवस के देही का एक दो चम्मच) कुछ ठंडी जगह रख दिया जाता है जो भोर तक ही में बदल जाता है। गृहणियों इसी शक्त करने का आभास दिताती हैं, और अनेक खनिज और विटामिन से परिपूर्ण होकर पाचन प्रणाली में



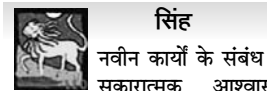
मेघ घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।



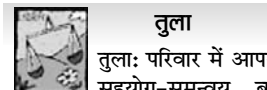
वृष परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोकि बना रहेगा।



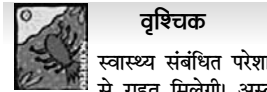
कर्क मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।



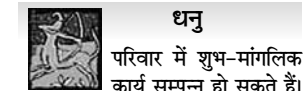
सिंह नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हूए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।



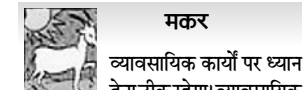
कन्या आय में वृद्धि होगी। धन प्राप्ति में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।



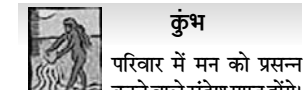
तुला: परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



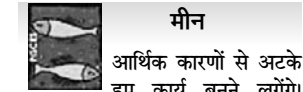
धनु परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मकर व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्थिति में सुधार होगा।



कुंभ परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा। परिवर्जनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



मीन आर्थिक कारणों से अटकें हूए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

विचार बिन्दु

असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर देती है।-हरिभाऊ उपाध्याय

देश का माहौल बदल रहा है

गत चार माह से देश के सामाजिक और राजनीतिक वातावरण में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। 1०-12 सालों से लगने लगा था कि देश अधिन्यायकवाद और तानाशाही की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है। लोग, सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोलने में डरने लगे थे। जो कोई भी साहस करके सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता, चाहे वह स्टैंड अप कॉमेडियन हो, शिक्षा विद हो, साहित्यकार हो या कलाकार ही क्यों न हो, उसकी आवाज को दबाने के लिए सरकार अपनी एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ते हुइ देवी गई। आई टी, ई डी और सी सी आई इस कार्य में सबसे अग्रणी रही। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी छवि बन गई कि देश में स्वतंत्र मत को व्यक्त करना कठिन होता जा रहा था। यह सब लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं थे।

जब सब कुछ निराशाजनक दिखाई दे रहा था, तभी एक छोटी सी घटना ने वातावरण को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया। एक केस की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 15 मई, 2०26 को युवाओं को कॉकरोच की सज़ा दे दी। इसी को आधार बनाकर अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने 16 मई, 2026 को “कॉकरोच जनता पार्टी” का गठन कर लिया। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक सप्ताह में ही दो करोड़ से अधिक फॉलोअर्स बन गए। प्रारंभ में इसे केवल सोशल मीडिया का बुलबुला माना जा रहा था। जब NEET परीक्षा के पेपर लीक होने के प्रकरण ने जोर पकड़ा तो अभिजीत दीपके, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए 6 जून 2०26 को भारत आया और दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रेस को संबोधित किया। कुछ समय देने के बाद भी जब सरकार ने प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया तो कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन आरम्भ कर दिया। इसमें अधिकांश GenZ अर्थात 14 से 29 वर्ष के युवा थे। इनके समर्थन में प्रख्यात शिक्षा विद और सामाजिक कार्यकर्ता सौनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ गये। यहां प्रतिदिन सैकड़ों, हजारों की संख्या में लोग देश के कई भागों से पहुंचने लगे। इसे कई संगठनों और राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त होने लगा।

छात्रों ने सुजनात्मकता का परिचय देते हुए कई नुक़्कड़ नाटक किए, गीत बनाए, मीम बनाए जिनमें मंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री पर भी व्यंग्य किए गए। ये सोशल मीडिया पर खूब चले, हालांकि इस बारे में कोई कवरेंज मुख्य धारा के मीडिया (जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है) द्वारा नहीं किया गया।

मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब 18 जुलाई की सुबह सौनम वांगचुक को बलपूर्वक आमरण अनशन से उठाकर अस्पताल में भरती करा दिया। उल्लेखनीय है कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक का मार्च निकालने का आह्वान किया गया था। इस दिन पुलिस ने अनशनरत छात्रों पर बहुत बल प्रयोग किया और उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस के अलावा ‘पैलेट गन’ का इस्तेमाल किया गया, हालांकि दिल्ली पुलिस इससे इनकार करती रही। राहुल गांधी एवं कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा इस मुद्दे को मीडिया और संसद में जोर शोर से उठाया गया जिसके कारण संसद नहीं चल पाई। राहुल गांधी द्वारा कई घंटों तक थाने में धरना देने के बाद मजबूरन दिल्ली पुलिस को पैलेट गन संबंधी एफ आई आर दर्ज करनी पड़ी।

जब सरकार को आंदोलन अपने नियंत्रण से बाहर होता दिखा तो सरकार के मंत्रियों ने जे पी नड्डा के नेतृत्व में सी जे पी के नेताओं के साथ वार्ता के बाद एक समझौता 25 जुलाई 2०26 को किया। इसके द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात मानी गई, आंदोलनकारियों पर कोई मुकदमा नहीं करने का आश्वासन दिया गया और दर्ज सभी एफ आई आर को वापस लेने की बात की गई। साथ ही, जिन परिवारों के बच्चों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक के कारण आत्महत्या की, उनको मुआवजा देने के प्रश्न पर भी समझौता हुआ।

समझौते के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो तुरंत करवा लिया गया, किंतु अन्य दो मांगों पर विशेष कार्रवाई नहीं हुई तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट फैसले में, संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी एफ आई आर निरस्त करने के आदेश दिए। यह आदेश देश के सभी राज्यों पर लागू किया गया।

कॉकरोच जनता पार्टी के अधिकांश आंदोलनकारी छात्र ‘जैन जी’ की परिभाषा में आते हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद नाम की 15 वर्षीय दलित छात्रा के पिता संजय कुमार का सिर स्वतंत्र भारद्वाज नामक व्यक्ति ने अपने कड़े के वार से फोड़ दिया था, जिससे, उसके ठंके आए। इसके बावजूद पुलिस ने हल्की धाराओं में एफ आई आर दर्ज की और वह कई दिन तक खुला घूमता रहा और शेखी बघारता रहा। न केवल यह, इस घटना के बाद उसने एक पॉडकास्ट में इस सारी घटना को स्वीकार भी किया और कहा कि उसने ‘हाफ मर्डर’ कर दिया, फिर भी उसके विरुद्ध किसी प्रचार की कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिल्ली पुलिस नहीं कर सकी, क्योंकि उसके निकट संपर्क केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा और भाजपा के अन्य बड़े-बड़े लोगों से हैं। उसका यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस प्रकरण में भी कॉकरोच जनता पार्टी ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और स्वतंत्र भारद्वाज पर एएससी एलटी एक्ट और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करने की मांग की गई। युवा लोगों के बढ़ते आक्रोश के कारण यहां भी अंततः पुलिस को स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार करना पड़ा और उस पर वे सभी धाराएं लगाई गईं, जिनकी सी जे पी मांग कर रही थी।

कुल मिलाकर, गत कुछ समय में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे नागरिकों में सरकार से जवाबदेही मांगने की प्रवृत्ति और साहस दोनों में वृद्धि हुई है। जब जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी तो शासन व्यवस्था में अपने आप सुधार आ जाएगा और वह आम नागरिक के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए।

हूए उसे गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लागू कर दिया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत किसी को जमानत भी नहीं मिल सकती है।

यह प्रकरण जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो वहां के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और अचल सचदेव की खंड पीठ ने एन एस ए की कार्यवाही को एकदम मरामना और अस्पष्ट मानते हुए रद्द कर दिया। यही नहीं, गलत हिरासत में रखने के लिए आकृति चौधरी को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। यूपीए की यह राशि नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम और अन्य अधिकारियों के हतन से वसूल करने के आदेश दिये। यह उल्लेखनीय है कि मेधा रूपम के पिता ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अतुल श्रीधरन वही न्यायाधीश थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में वहां के मंत्री विजय शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश तब दिए थे जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरेशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। इस आदेश के तुरंत बाद इनका स्थानांतरण मध्यप्रदेश से इलाहाबाद न्यायालय में कर दिया गया।

इन घटनाओं से यह तो स्पष्ट हो गया है कि नागरिकों को गुलाम या प्रजा मानने के स्थान पर, वास्तव में नागरिक समझना प्रारंभ कर दिया है। वे सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिखाने लगे हैं। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का काम कुछ निष्पक्ष और साहसी न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों से किया है। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं, यदि उनसे अपेक्षित कार्य करें, तो आम नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार का विरोध करने के अधिकार से उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। बस, केवल कुछ साहस की जरूरत थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से लोगों में उत्पन्न होने लगा है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को मुआवजा दिलाता कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि नहीं है। किंतु एक काम जो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हुआ है, वह, यह कि कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद, पूरे देश में युवा छात्र और बच्चे तक जिन्हें ‘जैन अल्फा’ कहा गया है, स्कूल की खराब स्थिति के बारे में खुलेआम बोलने लगे हैं और आंदोलन करने लगे हैं। कई स्थानों पर इसके कारण प्रशासन पर दबाव पड़ा और उन्होंने तुरंत फुरत में जरूर स्कूलों को गिराकर उनके स्थान पर नए स्कूल या कमरे बनाने के लिए न केवल राशि स्वीकृत की, बल्कि उसका काम भी प्रारंभ करवाया। इसी संदर्भ में, पाठकों के लिए यह जानना उपयुक्त होगा कि अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त, 2०26 से स्कूल टीका को अभियान चलाया है। इसके अंतर्गत कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के अलग-अलग भागों में अपने आसपास के सरकारी स्कूलों की स्थिति को देख रहे हैं और उसके बारे में वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत करा रहे हैं।

राजस्थान के रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल, जो भैंस के तबले में चल रहा था, वहां सी जे पी के आशुतोष राना ने जाकर वीडियो बना का प्रयास किया तो असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। इसके बावजूद प्रशासन को इसका संचालन लेना पड़ा और स्कूल को ठुडकाकर उसके स्थान पर नया स्कूल बनवाना प्रारंभ किया गया है। ऐसी स्थिति कई जगह सामने आई है जहां बच्चों के और युवाओं के दबाव में सरकार को स्कूलों से संबंधित काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

नागरिकों में सरकार विरोध का अनावश्यक डर निकल जाना एक बहुत बड़ी घटना है, जिसका दूरगामी प्रभाव होगा। कॉकरोच जनता पार्टी, एक नेतृत्व करने वाले ग्रुप के रूप में उभरी है। उन्हें केवल यह संयम बरतना होगा कि वह चुनावी राजनीति में न आए वरना उसका भी वही हश्र होगा जो आम आदमी पार्टी का हुआ।

सरकार को भी यह चाहिए कि वह विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने का काम करें। वर्तमान में तो स्थिति यहां तक हो गई है कि कोई विश्वविद्यालय यदि किसी ऐसे व्यक्ति को वक्तव्य रूप में बुला ले जो सरकार की नीति की आलोचना करता हो, तो संभव है, उसकी अनुमति ही नहीं मिले और मिल जाए तो उसे भी निरस्त कर दिया जाए।

छात्रों को ताकत कितनी है, इसका एक नमूना हैदराबाद के विधि विश्वविद्यालय NALSAR के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया, जब उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट कर दिया कि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत से डिग्री नहीं लेंगे और कन्वोकेशन में उन्हें नहीं बुलाया जाए। छात्रों के विरोध के बाद कन्वोकेशन निरस्त कर दिया गया और उन्हें डिग्री वैसे ही दे दी गई। जब बार कार्डसिल ऑफ इंडिया ने आंदोलनकारी छात्रों का पंजीकरण, बार कार्डसिल में नहीं करने का आदेश जारी किया तो उसे दो घंटे में ही वापस लेना पड़ा।

इन सारी घटनाओं से यह लगता है कि लोगों में अपनी बात कहने की हिम्मत आई है। प और यह भी उन्हें आसन्न हो गया है कि यदि वे अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसक आंदोलन करेंगे तो सरकार को उनकी बात को मानना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, गत कुछ समय में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे नागरिकों में सरकार से जवाबदेही मांगने की प्रवृत्ति और साहस दोनों में वृद्धि हुई है। जब जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी तो शासन व्यवस्था में अपने आप सुधार आ जाएगा और वह आम नागरिक के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आगे क्या होगा, चुनाव में क्या होगा, यह तो समय बताएगा। फिलहाल हम इतना तो कह ही सकते हैं कि देश का माहौल बदल रहा है।यह बदलाव किस रूप में किस सीमा तक होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

—**अतिथि संपादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)**

राशिफल मंगलवार 8 सितम्बर, 2026



पंडित अनिल शर्मा
बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह।

आज राजयोग सूर्योदय से दिन 2:43 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सायं 4:4० से सूर्योदय तक है। आज वी़छ बारस, वत्स द्वादशी, भौम प्रदोष व्रत है। आज से जैन पर्युषण (चतुर्थी पक्ष) आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौषड़ियाः चर 9:19 से 1०:52 तक, लाभ-अमृत 1०:52 से 1:57 तक, शुभ 3:3० से 5:०3 तक। राहुकालः 3:०0 से 4:30 तक, सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 6:36 पर